

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

एस.बी. मध्यस्थता आवेदन संख्या 23/2021

विमलेश बारेगामा पुत्र श्री ख्याली लाल बारेगामा, आयु लगभग 44 वर्ष,
निवासी बी-133, वीर सावरकर नगर, रंगबाड़ी रोड, कोटा (राज.) 324005

-----आवेदक

बनाम

मंगलम सीमेंट लिमिटेड अपने अध्यक्ष के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय
पी.ओ. आदित्य नगर-326520, मोराक, जिला कोटा (राज.)

-----प्रतिवादी

आवेदक के लिए	:	श्री विमलेश बारेगामा, याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित।
--------------	---	---

प्रतिवादी के लिए	:	श्री ऋषभ खंडेलवाल अधिवक्ता।
------------------	---	-----------------------------

एमिकस क्यूरी	:	श्री सुशील डागा, अधिवक्ता।
--------------	---	----------------------------

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

28/03/2024

1. आवेदक ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद '1996 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11(6) के तहत विवाद के अधिनिर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु एक

आवेदन प्रस्तुत किया है, जो आवेदक और गैर-आवेदक के बीच दिनांक 16.07.2012 के नियुक्ति पत्र के संदर्भ में उत्पन्न हुआ बताया गया है।

2. आवेदक का दावा है कि उसे शुरू में प्रतिवादी के साथ खरीद विभाग में सहायक के पद पर दिनांक 16.07.2012 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया था। आवेदन में कहा गया है कि नियुक्ति पत्र में एक शर्त यह थी कि आवेदक की सेवा से संबंधित सभी विवादों को अधिनिर्णय के लिए मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा आवेदक के विरुद्ध दिनांक 18.03.2020 को आरोप पत्र के माध्यम से शुरू की गई विभागीय जांच के परिणामस्वरूप, आवेदक को दिनांक 20.08.2020 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कलेक्टर को दिए गए प्रतिनिधित्व पर, विवाद को संयुक्त श्रम आयुक्त को संदर्भित किया गया, जिन्होंने दिनांक 11.09.2020 के आदेश द्वारा यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया कि उनके पास क्षेत्राधिकार नहीं था। अंततः मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए और एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए प्रतिवादी को एक नोटिस दिया गया। आवेदक ने मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए एक नोटिस भेजा और अपनी पसंद के एक मध्यस्थ को नामित किया। प्रतिवादी ने आवेदक द्वारा किए गए नामांकन से सहमत होने से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में, आवेदक ने दिनांक 16.07.2012 के अपने नियुक्ति

आदेश में निहित मध्यस्थता खंड के अनुसार एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया है।

3. उत्तर में, प्रतिवादी ने यह मामला प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने यह तथ्य छिपाना करते हुए आवेदन दायर किया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदक द्वारा कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद, आवेदक ने विवाद का समझौता किया और दिनांक 05.12.2020 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी कंपनी के साथ पूर्ण और अंतिम समझौता किया, जिसके तहत आवेदक ने अपने सभी विवादों के पूर्ण और अंतिम समझौते के लिए चेक स्वीकार किए, जिस पर आवेदक ने स्वयं विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किए थे। दिनांक 16.07.2012 के नियुक्ति पत्र के खंड संख्या 4(d) के अनुसार, कोई भी पक्ष तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले वेतन देकर नियुक्ति समाप्त कर सकता था। तीन महीने का वेतन पहले ही दिनांक 05.12.2020 के पूर्ण और अंतिम खाता समझौते में भुगतान किया जा चुका था, जिस पर आवेदक ने विधिवत हस्ताक्षर किए और स्वीकार किया था, इसलिए पक्षों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं है। दिनांक 05.12.2020 के पत्र की प्रति भी रिकॉर्ड पर रखी गई है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि आवेदक ने पूर्ण और अंतिम समझौते के लिए सभी चेक भुना लिए थे और भुगतान भी प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त सभी तथ्यों को छिपाना करते हुए, आवेदक ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। संक्षेप में,

प्रतिवादी का उत्तर यह है कि आवेदक ने सभी विवादों का समझौता किया, चेक प्राप्त किए और बिना किसी व्यवहार या विरोध के राशि को भुना भी लिया, इस आवेदन के माध्यम से उठाया गया विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य, तुच्छ और बाद में सोचा गया विचार है।

4. जबकि आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसे अवैध रूप से सेवा से बर्खास्त किया गया था और उसने सेवा से बर्खास्तगी के आदेश की शुद्धता और वैधता पर हमला करने के लिए विभिन्न आधार उठाए हैं, प्रतिवादी-गैर-आवेदक का मामला यह रहा है कि प्रथम दृष्टया, यह सभी दावों के पूर्ण और अंतिम समझौते के कारण एक गैर-मध्यस्थता योग्य विवाद है।
5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी को सुना है।
6. विचार के लिए उठने वाला मुद्दा यह है कि क्या, मामले के तथ्यों पर, सभी दावों के पूर्ण और अंतिम समझौते के कारण विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य है।
7. इससे पहले कि मैं मामले के तथ्यात्मक पहलुओं से निपटूं, विवाद की गैर-मध्यस्थता और विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के न्यायिक घोषणाएँ का उल्लेख करना उचित है।

8. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड, (2023) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 539 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले न्यायिक घोषणाएँ, विशेष रूप से विद्या द्रोलिया एंड अदर्स बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, (2021) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1 के मामले में निर्णय का सर्वेक्षण करने के बाद, निम्नानुसार अवलोकन किया: -

"73. इस न्यायालय के हाल के निर्णय में डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड बनाम राजापुरा होम्स (पी) लिमिटेड (2021) 16 एससीसी 743) जिसमें इस न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6-ए) पर विचार करने का भी अवसर मिला था और अंततः, विद्या द्रोलिया (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का संदर्भ और विचार करने के बाद, यह देखा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से यह पता लगाना है कि क्या विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच एक लिखित समझौता मौजूद था और क्या व्यथित पक्ष ने प्रथम दृष्टया तर्कसंगत मामला बनाया है, यह आगे देखा गया है कि सीमित क्षेत्राधिकार, हालांकि, न्यायालय को एक मध्यस्थता खंड के मात्र अस्तित्व से परे देखने के अपने न्यायिक कार्य से वंचित नहीं करता है ताकि अनावश्यक को हटाना जा सके। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विद्या द्रोलिया (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया था कि सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से, न्यायालय किसी भी तुच्छ या परेशान करने वाले दावे को बाहर करना के

लिए संदर्भ के चरण में 'प्रथम दृष्टया समीक्षा' कर सकता है।"

9. एनटीपीसी लिमिटेड बनाम एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड, (2023) 9 सुप्रीम कोर्ट केसेस 385 के मामले में एक अन्य निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार किया कि क्या यह एक मध्यस्थता योग्य विवाद था, उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में कि यद्यपि शुरू में पक्षों के बीच एक विवाद मौजूद था और एक रिट याचिका भी दायर की गई थी, पक्षों के बीच बातचीत एक समझौता समझौते में समाप्त हुई जिसके तहत एक पक्ष ने रोके गए बैंक गारंटी को जारी करने पर सहमति व्यक्त की और दूसरे पक्ष ने अपनी लंबित रिट याचिका वापस लेने पर सहमति व्यक्त की और विषय अनुबंध के तहत मध्यस्थता सहित कोई अन्य कार्यवाही शुरू न करने का वचन दिया। हालांकि, एक पक्ष द्वारा इसके कार्यान्वयन के बाद, दूसरे पक्ष ने समझौता समझौते को अस्वीकार करने की मांग की और समझौता समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव का आरोप लगाते हुए अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया।
10. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में और कानून के विकास और कानूनी स्थिति की जांच करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार समझाया गया: -

"16. कानून की स्थिति: वर्तमान मामले में, हम अधिनियम की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय के पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं और उस सीमित दायरे को रेखांकित करना चाहेंगे जिसके भीतर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन पर विचार किया जाना है।

17. पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार के संबंध में कानून की स्थिति, जैसा कि अधिनियम में धारा 11(6-ए) के आगमन से पहले मौजूद थी, इस न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोगारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड (2009) 1 एससीसी 267 में तैयार किए गए एक सुव्यवस्थित सिद्धांत पर आधारित थी। बोगारा पॉलीफैब में, इस न्यायालय ने माना कि विवाद की गैर-मध्यस्थता का मुद्दा उन मामलों में न्यायालय द्वारा जांचा जाना होगा जहां अनुबंध का समझौता और निर्वहन का आरोप लगाया गया है। बोगारा पॉलीफैब में सिद्धांत का पालन करते हुए, इस न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (2011) 12 एससीसी 349 में देखा कि जब एक निर्वहन वाउचर, कोई दावा नहीं प्रमाण पत्र या एक समझौता समझौते की वैधता विवाद में हो, तो न्यायालय को पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से पहले आरोपों की विश्वसनीयता की प्रथम दृष्ट्या जांच करनी चाहिए। फिर से न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एससीसी 424 में, इस न्यायालय ने देखा कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोपों को आरोप लगाने वाले पक्ष द्वारा साक्ष्य के माध्यम से प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित किया जाना चाहिए।

18. इन नज़ीर के लिए एक विधायी प्रतिक्रिया में, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6-ए) जोड़ी गई, जो इस प्रकार है:

11. (6-ए) सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रहेगा।"

(जोर दिया गया)

19. विधायी परिवर्तन का संज्ञान लेते हुए, इस न्यायालय ने इयूरो फेलगुएरा, एसए बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एससीसी 729 में नोट किया कि 2015 के संशोधनों के बाद, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार यह जांचने तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है - "न तो अधिक, न ही कम"।

20. हालांकि, वर्ष 2019 में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (2019) 5 एससीसी 362 में, इस न्यायालय ने फिर भी मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक आवेदन के विरोध में "समझौता और संतुष्टि" की आपत्ति को स्वीकार कर लिया था।

21. इस न्यायालय को एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) में दृष्टिकोण को उलटने में ज्यादा समय नहीं लगा। मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एससीसी 714 में एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से उपरोक्त संदर्भित निर्णय एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि: (मायावती ट्रेडिंग केस, एससीसी पृष्ठ 724-25, पैरा-10)

"10. यह स्थिति होने पर, यह स्पष्ट है कि 2015 के संशोधन से पहले का कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, अब विधायी रूप से रद्द कर दिया गया है। यह स्थिति होने पर, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि धारा 11(6-ए) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है और इसे इयूरो फेलगुएरा, एसए के निर्णय में निर्धारित संकीर्ण अर्थ में समझा जाना है।

(मूल में जोर दिया गया)

22. इस विषय पर संपूर्ण केस कानून पर विद्या द्रोल्या (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था, और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत निर्धारित किया गया था। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 120-21, पैरा 153-54)

"153. तदनुसार, हम मानते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में "मध्यस्थता समझौते का

अस्तित्व" अभिव्यक्ति में एक मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि न्यायालय संदर्भ के चरण में इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगा। बहस योग्य और विवादित तथ्यों के मामलों में, और अच्छे तर्कसंगत मामले आदि में, न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगा क्योंकि मध्यस्थ अधिकरण के पास क्षेत्राधिकार और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों का निर्णय करने का प्राथमिक क्षेत्राधिकार और अधिकार है।

154. "मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है?" शीर्षक के तहत चर्चा को निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है:

154.1. एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618 में निर्णय का अनुपात, अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर, अधिनियम 3 ऑफ 2016 (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से) द्वारा संशोधनों के बाद और यहां तक कि अधिनियम 33 ऑफ 2019 (9-8-2019 से प्रभावी) द्वारा संशोधनों के बाद भी, अब लागू नहीं है।

154.2. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायिक समीक्षा और न्यायालय के क्षेत्राधिकार का दायरा समान है लेकिन अत्यंत सीमित और प्रतिबंधित है।

154.3. सामान्य नियम और सिद्धांत, अधिनियम 3 ऑफ 2016 और अधिनियम 33 ऑफ 2019 से स्पष्ट विधायी जनादेश के मद्देनजर, और पृथक्करण और

सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांत के मद्देनजर, यह है कि मध्यस्थ अधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों का निर्धारण और निर्णय करने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकारी है। न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(2)(ए) के उप-खंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34(2)(बी) के उप-खंड (i) के संदर्भ में पुरस्कार के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी नज़र" की शक्ति प्रदान की गई है।

154.4. शायद ही कभी एक अवरोध के रूप में न्यायालय धारा 8 या 11 के चरण में हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और प्रथम दृष्टया निश्चित हो कि मध्यस्थता समझौता गैर-मौजूद, अमान्य है या विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति का निर्धारण करेगा। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से रोकने और अनावश्यक को हटाना के लिए है जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थता योग्य" हो। न्यायालय डिफॉल्ट रूप से मामले को संदर्भित करेगा जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित तर्क स्पष्ट रूप से तर्कसंगत हों; जब सारांश कार्यवाही में विचार अपर्याप्त और अनिर्णायक होगा; जब तथ्य विवादित हों; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष देरी की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है। यह न्यायालय के लिए एक मिनी परीक्षण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया जा सके बल्कि मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में पुष्टि और बनाए रखा जा सके।" (मूल और जोर दिया गया)

23. पूर्व-संदर्भ चरण में न्यायिक जांच का सीमित दायरा 'प्रथम दृष्टया समीक्षा' के परीक्षण के माध्यम से नेविगेट किया जाता है। इसे निम्नानुसार समझाया गया है: (विद्या द्रोलिया केस, एससीसी पृष्ठ 110-13, पैरा 133-34 और 138-40)

133. धारा 8 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामला पक्षों द्वारा प्रस्तुत मामले के गुणों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जिसे मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष स्थापित किया जाना है। यह एक वैध मध्यस्थता समझौते के तहत प्रथम दृष्टया मध्यस्थता योग्य होने के विषय-वस्तु तक सीमित है। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ है कि इन पहलुओं पर दावे सद्भावनापूर्ण हैं। पृथक्करण और सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांतों और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ने पर, संदर्भित न्यायालय बिना उलझे हुए पक्षों को पालन करने के लिए मजबूर करेगा जब तक कि इसके विपरीत अच्छे और पर्याप्त कारण न हों।

134. प्रथम दृष्टया जांच पूर्ण समीक्षा नहीं है बल्कि स्पष्ट रूप से और प्रथम दृष्टया गैर-मौजूद और अमान्य मध्यस्थता समझौतों और गैर-मध्यस्थता योग्य विवादों को बाहर करना के लिए एक प्राथमिक पहली समीक्षा है। संदर्भ चरण में प्रथम दृष्टया समीक्षा अनावश्यक को हटाना और सीधे मामलों में अनावश्यक को हटाना है जहां बर्खास्तगी स्पष्ट और पारदर्शी है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमा पहले चरण में ही रुक जाना चाहिए। केवल जब न्यायालय निश्चित हो कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या विवाद/विषय-वस्तु मध्यस्थता योग्य नहीं हैं, तो धारा 8 के तहत

आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर, न्यायालय को जटिलताएँ में नहीं खोना चाहिए और तथ्यों के बहस योग्य प्रश्नों का निर्णय नहीं करना चाहिए। संदर्भ कार्यवाही प्रारंभिक और सारांश है न कि एक मिनी परीक्षण...

138. दूसरी ओर, अनुबंध निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता से संबंधित मुद्दे संबंधित विवादों/ दावों के गुणों के अंतर्निहित मुद्दों से जुड़े और गुंथे हुए होंगे। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ अधिकरण को निर्णय लेना होगा।

139. हम बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, हालांकि यह देखेंगे कि न्यायालय वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है ताकि एक गहन लेकिन सारांश प्रथम दृष्टया समीक्षा की जा सके जबकि यह ध्यान में रखा जाए कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता करना है न कि मध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करना। संदर्भ चरण में एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या एक लंबी समीक्षा करना मध्यस्थता को एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में बाधित करेगा और देरी का कारण बनेगा जिससे अखंडता और प्रभावकारिता कमजोर होगी। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने में बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया जांच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय की चुनौती सही मात्रा और संदर्भ खोजना है जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगा या संयम बरतेगा। कानूनी व्यवस्था को संदर्भ चरण में मध्यस्थता में बाधा

डालने वाली रणनीति से बचने और पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो।

140. तदनुसार, जब यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक होगी, या विचार करने पर अपर्याप्त होगी क्योंकि इसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता है, तो मामला पक्षों द्वारा सहमति से चुने गए मध्यस्थ अधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अंतर्निहित तर्क यह है कि देरी या टालमटोल न करें और पक्षों को संदर्भ कार्यवाही का उपयोग देरी और बाधा डालने के बहाने के रूप में करने से हतोत्साहित करें। ऐसे मामलों में इस स्तर पर न्यायालयों द्वारा एक पूर्ण समीक्षा मध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करेगी और न्यायालयों और मध्यस्थ अधिकरण के बीच क्षेत्राधिकार आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। मध्यस्थ अधिकरण के साथ मुकदमेबाजी का केंद्रीकरण प्राथमिक और पहले अधिनिर्णायक के रूप में लाभकारी है क्योंकि यह विवादों के त्वरित और कुशल समाधान में मदद करता है।"

(जोर दिया गया)

विभिन्न न्यायिक घोषणाएँ और प्रथम दृष्टया परीक्षण के सामान्य सूत्र के माध्यम से नेविगेट करने के बाद, इसे निम्नानुसार आधिकारिक रूप से आयोजित किया गया था: -

24. विद्या द्रोलिया में निर्धारित सामान्य नियम और सिद्धांत का पालन करते हुए, इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि मध्यस्थ अधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों का निर्धारण और निर्णय करने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकारी है। प्रवीण इलेक्ट्रिकल (पी) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड (2021) 5 एससीसी 671, संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा (2021) 9 एससीसी 732 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड (2023) 2 एससीसी 539 में, पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था, क्योंकि गैर-मध्यस्थता की आपत्ति पर इनमें से प्रत्येक मामले में प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक पाई गई थी। सामान्य सिद्धांत के अपवाद का पालन करते हुए कि न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं कर सकता है जब यह स्पष्ट हो कि मामला स्पष्ट रूप से और प्रथम दृष्टया गैर-मध्यस्थता योग्य है, बीएसएनएल बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (2021) 5 एससीसी 738 (इसके बाद "नॉर्टेल नेटवर्क्स") और सिकंदराबाद छावनी बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस (2021) 5 एससीसी 705 में, मध्यस्थता से इनकार कर दिया गया था क्योंकि पक्षों के दावे स्पष्ट रूप से समय-बाधित थे।

सूक्ष्म जांच

25. उपरोक्त संदर्भित नज़ीर कानून की स्थिति को क्रिस्टलीकृत करते हैं कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत न्यायालयों का पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार बहुत संकीर्ण है और इसमें दो जांच शामिल हैं। प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है, जिसमें समझौते के पक्षों और उक्त समझौते के लिए आवेदक की गोपनीयता के बारे में भी एक जांच शामिल है। ये ऐसे मामले हैं जिनके लिए संदर्भित न्यायालय द्वारा गहन जांच की आवश्यकता होती है। द्वितीयक जांच जो संदर्भ चरण में ही उत्पन्न हो सकती है, विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है।
26. एक सामान्य नियम और सिद्धांत के रूप में, मध्यस्थ अधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों का निर्धारण और निर्णय करने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकारी है। नियम के अपवाद के रूप में, और शायद ही कभी एक अवरोध के रूप में, संदर्भित न्यायालय उन दावों को अस्वीकार कर सकता है जो स्पष्ट रूप से और प्रथम दृष्टया गैर-मध्यस्थता योग्य हैं। इस स्थिति को समझाते हुए, विद्या द्रोनिया (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों से उत्पन्न होते हुए, इस न्यायालय ने नॉर्टेल नेटवर्क्स (सुप्रा) में एक बाद के निर्णय में कहा: (नॉर्टेल नेटवर्क्स केस, एससीसी पृष्ठ 764, पैरा 45)

"45. ..45.1. ... धारा 11 के तहत न्यायिक मंच के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय स्पष्ट रूप से योग्यताहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी को स्क्रीन करने और गिराने के लिए

प्रथम दृष्टया परीक्षण का प्रयोग कर सकता है। न्यायालयों का सीमित क्षेत्राधिकार संदर्भ चरण में त्वरित और कुशल निपटान सुनिश्चित करेगा। संदर्भ चरण में, न्यायालय "केवल" तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह "स्पष्ट" हो कि दावे स्पष्ट रूप से समय-बाधित और मृत हैं, या कोई मौजूदा विवाद नहीं है।"

27. दावे की गैर-मध्यस्थता की जांच करने का जांच का मानक केवल प्रथम दृष्टया है। संदर्भित न्यायालयों को विवादित तथ्यों की पूर्ण समीक्षा नहीं करनी चाहिए; उन्हें केवल एक प्राथमिक पहली समीक्षा तक सीमित रहना चाहिए और तथ्यों को स्वयं बोलने देना चाहिए। इसके लिए न्यायालयों को यह भी जांचने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता पर दावा सद्भावनापूर्ण है या नहीं। तथ्यों की प्रथम दृष्टया जांच से एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलना चाहिए कि दावे की गैर-मध्यस्थता के बारे में संदेह का कोई निशान नहीं है। दूसरी ओर, यदि थोड़ा सा भी संदेह है, तो नियम विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना है।

28. सूक्ष्म जांच, आवश्यक और बाध्यकारी है। यह संदर्भित न्यायालय के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है कि वह पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाए जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो। इसे सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए संदर्भ से इनकार करने के लिए न्यायालयों द्वारा एक वैध हस्तक्षेप के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि विद्या द्रोलिया

में नोट किया गया है, यदि सीमित दायरे में इस कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न्यायालय हस्तक्षेप करने में बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। इसलिए, यह न्यायालय या एक उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, केवल एक आवेदक द्वारा उठाए गए कथित विवाद को चुने हुए मध्यस्थ के दरवाजे पर पहुंचाने के लिए यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड बनाम राजापुरा होम्स (पी) लिमिटेड (2021) 16 एससीसी 743 में समझाया गया है।"

11. मैजिक आई डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स ग्रीन एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, (2023) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 50 के मामले में एक और हालिया न्यायिक घोषणा में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गईं: -

"8. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6-ए) जिसे मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से जोड़ा गया है, को पढ़ा जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

"11. (6-ए) सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रहेगा।" (जोर दिया गया)

9. इस प्रकार, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार यह जांचने तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है - "न तो अधिक, न ही कम"। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11(6-ए) के अनुसार, यह संदर्भित न्यायालय पर एक कर्तव्य है कि वह एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में विवाद/मुद्दे पर विचार करे।

10. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत न्यायालय का पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार बहुत संकीर्ण है और इसमें दो जांच शामिल हैं। प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है, जिसमें समझौते के पक्षों और उक्त समझौते के लिए आवेदक की गोपनीयता के बारे में भी एक जांच शामिल है। उक्त मामले के लिए संदर्भित न्यायालय द्वारा गहन जांच की आवश्यकता होती है। (एनटीपीसी के निर्णय का पैरा 25)। द्वितीयक जांच जो संदर्भ चरण में ही उत्पन्न हो सकती है, विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है। दोनों अलग और विशिष्ट हैं।"

29. यदि उपरोक्त हाल के न्यायिक घोषणाएँ में लगातार निर्धारित कानून को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू किया जाता है, तो हम पाते हैं कि आवेदक ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है, यह दर्शाते हुए कि पक्षों के बीच एक विवाद मौजूद है, जबकि, प्रतिवादी के उत्तर से, यह पता चलता है कि आवेदक के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम समझौता किया गया है, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दायर जोरदार और विशिष्ट उत्तर से स्पष्ट होगा जिसमें, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पक्षों ने दिनांक 05.12.2020 के पत्र के माध्यम से पूर्ण और अंतिम समझौता किया है जिसके तहत, आवेदक ने चेक स्वीकार किए। दिनांक 05.12.2020 का पत्र आवेदक को जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्ण और अंतिम समझौते के लिए चेक उसके पक्ष में जारी किए गए हैं। कुल 3,92,809/- रुपये की राशि के लिए दिनांक 03.12.2020 के चार चेक आवेदक के पक्ष में जारी किए गए थे। आवेदक ने न केवल रसीद स्वीकार की जो उसके हस्ताक्षर से स्पष्ट है, बल्कि विभिन्न चेकों के तहत राशि को भुनाने के लिए भी आगे बढ़ा।
30. पूर्ण और अंतिम समझौते के लिए 3,92,809/- रुपये के चार चेक स्वीकार करने के बाद, आवेदक ने सुविधापूर्वक इस न्यायालय के समक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, चेक प्राप्त करने और पूर्ण और अंतिम समझौते के लिए उन्हें भुनाने के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना और छिपाना। पूर्ण

और अंतिम समझौते के लिए चेक स्वीकार करने और भुनाने के संबंध में आवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर दायर होने के बाद भी, किसी हलफनामे द्वारा समर्थित कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है।

31. मैजिक आई डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में निर्णय की प्रति के साथ लिखित निवेदन दायर करते समय और मैसर्स मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन (सिविल अपील संख्या 7023 ऑफ 2019, दिनांक 05.09.2019 को निर्णय लिया गया) के मामले में निर्णय की प्रति और कुछ दस्तावेज बिना किसी हलफनामे द्वारा समर्थित किए, एक बार जब आवेदक को यह उजागर किया गया कि समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना करके, आवेदन बाद में सोचे गए आधार उठाने के लिए दायर किया गया था, तो समझौते से बचना का प्रयास किया गया है।

32. एनटीपीसी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, विवाद का समझौता करने के बाद, एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए विभिन्न आधारों पर एक आवेदन दायर किया गया था ताकि समझौते से बचना जा सके, समझौता समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव का आरोप लगाते हुए। हाथ में मामले की जांच करने पर, सर्वोच्च न्यायालय में उनके लॉर्डशिप ने निष्कर्ष निकाला कि

जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोप सद्भावनापूर्ण नहीं थे और पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए कोई लंबित दावे नहीं थे। यह आगे देखा गया कि विलंबित और बाद में सोचा गया विचार इस विवरण में फिट बैठता है कि यह "स्पष्ट रूप से योग्यताहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी" शुरू करने का एक प्रयास था, जिसके बाद ऐसे निष्कर्ष के कारण बताए गए। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत बयानी या आर्थिक दबाव का कोई आरोप भी नहीं उठाया गया है, जिसके लिए सूक्ष्म जांच की आवश्यकता हो। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां आवेदक ने समझौते से संबंधित तथ्य को पूरी तरह से छिपाना किया है। चीजें अलग होतीं यदि आवेदक ने जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत बयानी या आर्थिक दबाव का आरोप लगाया होता, जैसा कि उस पृष्ठभूमि में जिसमें उसने उसे दिए गए और उसके द्वारा स्वीकार किए गए चार चेक स्वीकार किए और भुनाए थे। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाला आवेदन पक्षों के बीच समझौते से संबंधित तथ्य को छिपाना पर आधारित है।

33. उपरोक्त के मद्देनजर, मेरा विचार है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां आवेदक ने सभी विवादों का समझौता किया है और अपने सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि के लिए चार चेक स्वीकार किए और उन्हें भुना भी लिया, एक मध्यस्थता की मांग करता है।

वर्तमान स्पष्ट रूप से एक गैर-मध्यस्थता योग्य विवाद है और आवेदन उतना ही तुच्छ है जितना हो सकता है। इसलिए, मैं आवेदन को खारिज करने के लिए इच्छुक हूँ। मामले को समाप्त करने से पहले, मैं विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करता हूँ।

34. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायाधीश

संजय कुमावत-14

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

